राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 9(5)(5)पार्ट—ा / एन.एस.ए.पी. / सा.च्या.अ.वि. / 08-09 / जयपुर, दिनांक : २५५१००/

आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन्दिश गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (IGNDPS) दिनांक 17.2.09 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित पात्रता के निशक्तजनों को रूपये 400/— प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है:—

"भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य हैं।

भारत सरकार के पत्रांक जे—11013/2/07—एनएसएपी दिनांक 17,2.09 एवं इस संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक जे—11012/1/09—एनएसएपी दिनांक 30.9.09(प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त दिशा—निर्देशानुसार इस योजना के अन्तर्गत लामान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा—निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 02 को उपयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लामान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को तुरन्त प्रभाव से राज्य में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।



इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित निःशक्तजन को कुल व्यय पेंशन राशि रूपये 400/— प्रतिमाह में से भारत सरकार के हिस्से की राशि रूपये 200/— प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा:—

2235—	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
(01)—	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[08,]-	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन
24-	पेंशन और उपदान(आयोजना)

राज्य सरकार के हिस्से की राशि रूपये 200/- प्रतिमाह का भुगतान निम्नांकित बजट मद से उपलब्ध प्रावधान में किया जायेगा:-

	The company of the large water to the contract of the contract
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
(01)—	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[02]-	अंगहीन एवं दृष्टिहीन निराश्रितो को पेंशन
24-	पेंशन और उपदान(आयोजना भिन्न)

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि-

- 1. इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगाः—
- (i) अंधता
- (ii) कम दृष्टि
- (iii) कुष्ठ रोग मुक्त
- (iv) श्रवण शक्ति का हास
- (v) चलन निःशक्तता
- (vi) मानसिक मंदता
- (vii) मानसिक रूग्णता



2. ऐसे निःशक्तजन जो राजस्थान अपाहिज,अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे है और जिनकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य है तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना ((IGNDPS) के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते पूर्ण करते है उन्हें चिन्हित कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना ((IGNDPS) स्थानान्तरित कर उपरोक्तानुसार पेंशन का भुगतानं किया जायेगा।

3. राजस्थान अपाहिज,अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे अंधता एवं चलन निःशक्तता संबंधी पात्र लाभार्थी पूर्वानुसार लाभ प्राप्त करते रहेंगे एवं वर्तमान शर्तो पर भविष्य

में भी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ दिया जावेगा।

यह आदेश वित्त व्यय-2 विभाग के अ.शा. टीप 100904093 दिनाक 17.11.09 के द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते है।

आयुक्त एवं शासन सचिव क्रमांक : एफ ९(६)(६)पार्ट-ा / एन.एस.ए.पी. / सा.न्या.अ.वि. / 08-09 / जयए ४९६५ - ९०१८/ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-जयपुर, दिनांक :24-11-09

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।

2.प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर

- 3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विमाग, राजस्थान, जयपूर।
- 4 उप शासन सचिव, वित्त (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- उप सिवव (जे), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्यमंत्री_कसाऱ्या.अ.विभाग, जयपुर।
- सन्मागीय आयुक्त (समस्त)।

निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साऱ्या अविभाग, जयपुर।

- 9. समस्त जिला कलेक्टर्स को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय समसंख्यक पत्रांक 1844-76 दिनांक 27.02.09 द्वारा आपको मारत सरकार के पत्रांक जे-11013/02/2007/एन.एस.ए.पी./दिनांक 17. 02.09 की प्रति पूर्व में मिजवाई जा मुकी है। अतः कृपया उपर्युक्त पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले निःशक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उक्त पेंशन योजना का लाम अविलम्ब दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों की प्रति अपने अधीनस्थ पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (समस्त उप खण्ड अधिकारी) को मिजवाना सुनिश्चित करें।
- 10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

12. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,, समस्त जिला परिषद को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त पेशन योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले निःशक्त व्यक्तियों को धिन्हित कर उक्त पेशन योजना का लाभ अविलम्ब दिया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा इन आदेशों की प्रति अपने अधीनस्थ पॅशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (समस्त विकास अधिकारी) को भिजवाना सुनिश्चित करें।

13. परियोजना निदेशक, (एस.सी.एस.पी.), सा.न्या.अ.विभाग, जयपुर।

14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

15. समस्त कोषाधिकारी..

16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परि. एवं स.क.अधिकारी, सा.न्या.अ.विभाग Blem weca

र मुख्य लेखाविकारी अपा

No. J-11012/1/2009-NSAP Government of India Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi Dated: 30th September, 2009

OFFICE MEMORANDUM

pubject: Guidelines for central assistance under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) as part of the National Social Assistance Programme(NSAP).

Name of the Scheme

The scheme is known as 'Indira Gandhi National Disability Pension Scheme' GNDPS). It comes into existence from February 2009.

Eligibility criteria of Beneficiary

- (A) For purpose of claiming central assistance, the following criteria shall apply:
- (i) The age of disabled shall be between 18-64 years.
- (ii) The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India
- (iii) The applicant should be suffering from severe or multiple disabilities as defined in Persons with Disabilities Act, 1995 (PWD Act 1995) and the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999(National Trust Act 1999) revised from time to time and any other guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment in this regard.
- (B) For the purpose of defining severe or multiple disabilities the following may be considered:-
- (i) As per clause (i) of section 2 of the PwD Act, 'Disability' means (i) blindness, (ii) low vision, (iii) leprosy cured, (iv) hearing impairment, (v) loco motor disability, (vi) mental retardation and (vii) mental illness.
- (ii) As per clause (t) of section 2 of the PwD Act, 'persons with disability' means a person suffering from not less than forty percent of any disability as certified by medical authority.

- As per clause (4) of section 56 of the PwD Act, "Persons with severe (iii) disability" means a person with eighty percent or more of one or more
- As per clause (h) of section 2 of the National Trust Act, 'Multiple (iv) Disabilities' means combination of two or more disabilities as defined in clause (i) of section 2 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995.
- For the purpose of certification of disabilities covered under the scheme, (C) the following may be considered:-(i)
- The applicant shall submit a medical certificate from 'medical authority' as per the provision of clause (p) of Section 2 of the PwD Act and para B (ii)
- The findings of the competent medical authority on the extent of disability (ii) would be treated final.
- The State Government will facilitate in obtaining the certificate of severe or (D) multiple disability of such persons who applies for assistance under the scheme by inviting the medical authority at Block/ Tehsil/ Mandal level or as admissible so that distance may not act as deterrent and such persons do not face

111 Amount of pension

The Central assistance under IGNDPS will be provided at the rate of Rs.200 per month per beneficiary. The State Governments are urged to contirbute at least equally IV

Specific condition regarding sanction of pension

Sanction of pension to a beneficiary has to be made only after placing the database of beneficiary in the public domain/ website of the Ministry or State.

Mode of payment

The pension is to be credited into a post office or public sector bank account of the beneficiary.

VI Identification of beneficiary

The Gram Panchayat/ Municipalities are expected to play an active role in identification of beneficiaries under the Scheme.

Certificate of coverage

The States/ UTs are required to furnish a certificate that all eligible disabled have been covered under IGNDPS.

Number of eligible beneficiaries under IGNDPS VIII

The number of eligible beneficiaries to be assisted under IGNDPS will be determined as per the field report of all the beneficiaries who satisfy the eligibility criteria

™IX Allocation of funds

The funds for operation of the scheme relating to IGNOAPS, IGNDPS, IGNWPS, The funds for operation of the scheme relating to rotton and National Family Benefit Scheme as part of National Social Assistance Programme and Annapurna will continue to be released in a combined manner.

(Nilam Sawhney)

Joint Secretary to the Government of India

Secretary (in charge of NSAP) All States/Union Territories

minim

No. J-11015/1/2011-NSAP Government of India Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi Dated June, 30,2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) issued vide O.M. No. J-11012/1/2009-NSAP dated 30th September 2009. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the beneficiary shall be in the age group of 18-64 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. As a result of decision of the Government of India to lower the age limit from 65 years to 60 years under the ongoing Indira Gandhi National Old Age Pension(IGNOAPS), it has been decided to modify the eligibility criteria for disability pension under IGNDPS as follows -

Eligibility Criteria

(A)For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

- The age of the disabled shall be between 18-59 years.
- The applicant must belong to a household below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.
- 3. The other provisions regarding the 'Eligibility Criteria', 'Amount of Pension', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. No. dated 30th September 2009.

(Sanjay Kumar Rakesh)
Joint Secretary to the Government of India

Secretary In-charge of NSAP All States/ Union Territories PA

No. J-11015/ 1 /2012-NSAP Government of India Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi Dated: 8th November, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the National Family Benefit Scheme (NFBS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of National Family Benefit Scheme (NFBS) issued in 1998. The specific conditions mentioned in the para 22(ii) of guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the death of such primary breadwinner should have than 65 years of age.

2. Government of India has decided to revise the eligibility age from 18-64 years to 18-59 years under the ongoing National Family Benefit Scheme (NFBS) and also increase the lump sum grant under NFBS from Rs. 10000/- to Rs. 20000/-. The revised norms will come into effect from 18.10.2012. Accordingly, the revised criteria for assistance under NFBS would be as under:-

I Eligibility Criteria

- (22) For purposes of determining Central assistance, the following criteria shall apply:
 - i) The 'primary breadwinner' will be the member of the household- male or female- whose earning contribute substantially to the total household income.
 - The death of such a primary breadwinner should have occurred while he or she is in the age group of 18 to 59 years i.e. more than 18 years of age and less than 60 years of age.
 - The bereaved household qualifies as one below the poverty line according to the criterion prescribed by the Government of India.
 - The Central Assistance under the scheme will be Rs. 20000/- in the case of death of the primary breadwinner.
- The other provisions will remain the same as mentioned in the Guidelines issued in 1998.

(VIJAYA SRIVASTAVA

Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP
All States/ Union Territories

No. J-11015/1/2012-NSAP Government of India Ministry of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi Dated: November 8, 2012

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Guidelines for Central assistance under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS).

The undersigned is directed to refer to the guidelines of Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) issued vide O.M. No. J J-11015/1/2011-NSAP dated 30th June 2011. The eligibility criteria mentioned in the guidelines for the purpose of claiming central assistance was that the beneficiary shall be in the age group of 18-59 years and must belong to a household living below the poverty line according to the criteria prescribed by the Government of India.

2. Government of India has decided to revise the eligibility age from 40-59 years to 40-79 under the ongoing Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) and also to increase the rate of assistance from Rs. 200/- to Rs. 300/-. The revised norms will come into effect from 1.10.2012. Accordingly, the revised criteria for grant of pension under IGNDPS would be as under:-

I Eligibility Criteria

8

(A)For purpose of claiming Central assistance, the following criteria shall apply:

i) The age of the disabled shall be between 18-79 years.

II Amount of pension

The Central Assistance under IGNDPS will be provided at the rate of Rs. 300 per month per beneficiary.

3. The other provisions regarding the 'Eligibility Criteria', 'Certificate of Coverage', 'Allocation of Funds' etc. will remain the same as mentioned in the O.M. dated 30th June 2011.

(VIJAYA SRIVASTAVA)

Joint Secretary to the Government of India

Secretary
In-charge of NSAP
All States/ Union Territories